Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X (Print), Impact Factor: (Cosmos: 7.866 & I2OR: 5.675) Volume 16, No. 01, January-March, 2026, pp. 125-134

डिजिटल मीडियाः आदिवासी महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम

विजय सिंह*

शोधार्थी, बनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान।

*Corresponding Author: vijayahirindian@gmail.com

Citation: *सिंह, विजय (2026). डिजिटल मीडियाः आदिवासी महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम. Journal of Modern Management & Entrepreneurship, 16(01), 125–134.*

सार

डिजिटल मीडिया आदिवासी महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य को पुनर्गठित करने में परिवर्तनकारी उत्प्रेरक के रूप में उभरा है। यह शोधपत्र डिजिटल मीडिया के बहुआयामी सशक्तिकरण तंत्रों की जांच करता हैकृ जिसमें सामाजिक नेटवर्किंग प्लेटफार्मों, ई–कॉमर्स उपकरणों और डिजिटल वित्तीय सेवाएं शामिल हैं, जो आदिवासी महिलाओं की एजेंसी, निर्णय लेने के अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता में मूर्त सुधार हेतु सुविधा प्रदान करते हैं। क्षमता सिद्धांत, एजेंसी–आधारित दृष्टिकोण और भागीदारी संचार मॉडलों को संयोजित करने वाली एक समन्वित रूपरेखा के माध्यम से, यह शोधपत्र प्रदर्शित करता है कि डिजिटल मीडिया परंपरागत रूप से अलग–थलग आदिवासी समुदायों और अवसर, सूचना पहुंच और बाजार भागीदारी के व्यापक नेटवर्कों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करता है। शोध चार प्राथमिक सशक्तिकरण मार्गों की पहचान करता हैः जानकारी पहुंच से जागरूकता और अधिकार चेतनाय वित्तीय समावेशन जो डिजिटल उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता सक्षम करता हैय कौशल विकास जो रोजगार संभावनाएं और डिजिटल साक्षरता सुविधा प्रदान करता हैय और सामाजिक नेटवर्किंग जो सामूहिक एजेंसी और सामुदायिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। डिजिटल मीडिया तक पहुंच रखने वाली एवं उपयोग करने वाली आदिवासी महिलाएं विभिन्न प्लेटफार्मों को आय सृजन, व्यावसायिक कार्य , संचार और सूचना खोज के लिए नियोजित करती हैं। हालांकि, सीमित डिजिटल साक्षरता, अपर्याप्त अवसंरचना, लिंग–आधारित पहुंच प्रतिबंध और सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएं बनी रहती हैं। अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि डिजिटल मीडिया शक्ति संबंध को रूपांतरित करने और पितृसत्तात्मक संरचनाओं को तोड़ने के अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत करता है फिर भी सतत सशक्तिकरण के लिए पूरक नीति हस्तक्षेप, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, अवसंरचना विकास और सामुदायिक आधारित समर्थन तंत्र की आवश्यकता है। डिजिटल मीडिया का लक्षित कौशल विकास पहलों के साथ कौशल संयोजन आदिवासी महिलाओं में परिवर्तनकारी एजेंसी को प्रेरित कर सकता है, उन्हें व्यक्तिगत, घरेलू और सामुदायिक क्षेत्रों में सार्थक विकल्प का उपयोग करने में सक्षम करता है, साथ ही सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक समन्वय को संरक्षित करता है।

शब्दकोशः *डिजिटल मीडिया, आदिवासी महिला सशक्तिकरण, सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक स्वतंत्रता, एजेंसी, क्षमता दृष्टिकोण, सामाजिक मीडिया उद्यमिता, लैंगिक समानता, डिजिटल विभाजन।*

* *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

प्रस्तावना

समकालीन समाज में डिजिटल मीडिया के सर्वव्यापी उदय ने भारत के विविध समुदायों में सामाजिक संपर्क, आर्थिक भागीदारी और सूचना पहुंच के परिदृश्य को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया है। हालांकि, इस डिजिटल क्रांति के लाभ असमान रूप से वितरित रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहने वाली आबादियांकृ विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों की आदिवासी महिलाएं, सार्थक डिजिटल संलग्नता के लिए निरंतर बाधाओं का सामना कर रहीं हैं। भारत में आदिवासी समुदाय कुल आबादी का लगभग 8.6% प्रतिनिधित्व करते हुए, देश के आर्थिक रूप से वंचित और सामाजिक रूप से अलग थलग समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन समुदायों के अंदर महिलाएं एक विशेषतः कमजोर स्थिति में रहती हैं, जो लैंगिक असमानता और पितृसत्तात्मकता से उत्पन्न भेदभाव का निरन्तर सामना करती हैं।

राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा जिला आदिवासी महिलाओं द्वारा विकास अवसरों तक पहुंचने में सामना की जाने वाली जटिल चुनौतियों का एक उदाहरण है। जिले की आबादी का लगभग 76% आदिवासी (मुख्यतः भील, गरसिया और अन्य जनजातीय समुदाय) होने के साथ, बांसवाड़ा जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के रूप में एक भौगोलिक स्थान और उदीयमान डिजिटल परिवर्तन की साइट दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इस जिले की कॉलेज–जाने वाली आदिवासी महिलाएं अद्वितीय परिस्थितियों का सामना करती हैंः वे एक साथ पारंपरिक रिश्तेदारी संरचनाओं, लैंगिक अपेक्षाओं जो उनकी गतिशीलता और स्वायत्तता को सीमित करती हैं, आर्थिक संसाधनों तक सीमित पहुंच और सीमित उपलब्ध डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर रही हैं जो पारंपरिक शक्ति व्यवस्थाओं को चुनौती देती हैं।

इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, विभिन्न डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म आदिवासी महिलाओं के जीवन की परिस्थितियों को रूपांतरित करने के लिए नई संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सामाजिक मीडिया नेटवर्कोंय डिजिटल वित्तीय सेवाएंय और ऑनलाइन उद्यमिता उपकरण शामिल हैं। डिजिटल मीडिया को एक तटस्थ तकनीक के रूप में देखने के बजाय, यह शोध इसे असमान शक्ति संबंधों के विरुद्ध एक उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करता है, जो मौजूदा असमानताओं क`खिलाफ लैंगिक–सचेत दृष्टिकोण उत्पन्न कर सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। जैसे–जैसे आदिवासी समुदाय तीव्र डिजिटलीकरण का अनुभव कर रहे हैं, गंभीर प्रश्न उभरने लगें हैंः डिजिटल प्लेटफार्मों आदिवासी महिलाओं की एजेंसी और निर्णय लेने की क्षमता को विस्तारित करने के लिए साधनों के रूप में कैसे कार्य करते हैं? डिजिटल मीडिया किन तंत्रों के माध्यम से सूचना की कमी से सूचित चेतना में संक्रमण सुविधा प्रदान करता है ? कौन सी बाधाएं सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट आदिवासी संदर्भों में डिजिटल तकनीकों की सशक्तिकारी क्षमता को सीमित करती हैं? नीति ढांचों और सामुदायिक गतिशीलता के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण प्रक्रियाओं को कैसे बनाए रखा जा सकता है? यह शोध सशक्तिकरण के सैद्धांतिक ढांचों को आदिवासी महिलाओं के बीच डिजिटल मीडिया के परिवर्तनकारी प्रभावों के साथ संश्लेषित करके इन अंतर्संबंधित प्रश्नों को संबोधित करता है।

सैद्धांतिक रूपरेखाः सशक्तिकरण और डिजिटल एजेंसी का विचार

महिला सशक्तिकरण–एजेंसी और विकल्पः महिला सशक्तिकरण विकास प्रवचन में एक विवादास्पद फिर भी आवश्यक अवधारणा का गठन करता है, जो पहुंच या भागीदारी के सतही मापों से कहीं अधिक को समाहित करता है। नैला कबीर, सशक्तिकरण को ष्लोगों की रणनीतिक जीवन चुनाव करने की क्षमता में विस्तारष् के रूप में समझाते है। यह परिभाषा तीन अंतर्संबंधित आयामों पर जोर देती हैः संसाधन (विकल्प को सक्षम करने वाली संपत्ति और क्षमताएं), एजेंसी (जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से विकल्प लागू किए जाते हैं) और उपलब्धियां (प्रयोग की गई विकल्पों से प्राप्त परिणाम)। आलोचनात्मक रूप से, इस रूपरेखा की मान्यता है कि सशक्तिकरण कई क्षेत्रों में संचालित होता हैकृव्यक्तिगत, घरेलू, सामुदायिक और सामाजिक, जो चेतना, क्षमताओं और संरचनात्मक

परिस्थितियों में परिवर्तन को विकल्प–निर्माण के रुप में सक्षम करते हुए शामिल करता है। आदिवासी महिलाओं के संदर्भों में, सशक्तिकरण जीवन–निर्वाह–उन्मुख निर्णय लेने से परे उत्कर्ष का प्रतीक है जिसे कबीर ष्रणनीतिकष् या ष्परिवर्तनकारीष् विकल्प–निर्माण के रूप में अलग करते हैं। निष्क्रियता से सक्रिय एजेंसी की ओर यह प्रगति आदिवासी महिलाओं को केवल मौजूदा पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं करने, बल्कि शक्ति संबंधों को स्वयं प्रश्नचिह्नित और पुनर्निर्माण करने को शामिल करता है।

क्षमता दृष्टिकोण, अमर्त्य सेन की विश्लेषणात्मक रूपरेखा को विस्तारित करते हुए, कार्यक्षमता (जो व्यक्ति वास्तव में प्राप्त करते हैं) और क्षमताओं (जो वे वास्तव में करने या बनने में सक्षम हैं) को सामने रखकर पूरक सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है।

बहुआयामी सशक्तिकरण – परिवर्तन के अंतर्संबंधित क्षेत्रः समकालीन सशक्तिकरण अवधारणा की मान्यता है कि परिवर्तन अंतर्संबंधित आयामों में एक साथ बदलावों के माध्यम से उत्पन्न होता है। आदिवासी संदर्भों में महिला सशक्तिकरण पर शोध सात प्राथमिक आयामों की पहचान करता हैः आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, कानूनी, और डिजिटल। ये आयाम विभाजित नहीं हैं बल्कि पारस्परिक रूप से सुदृढ़ करने वाले हैं। आर्थिक सशक्तिकरणकृआय सृजन, उद्यमिता, संपत्ति संचय और बाजार पहुंच को समाहित करते हुएकृअन्य सशक्तिकरण क्षेत्रों में भागीदारी के लिए भौतिक आधार बनाता है। सामाजिक सशक्तिकरण सामुदायिक संस्थाओं में भागीदारी में वृद्धि, घरेल ूनिर्णय की शक्ति और उच्च सामाजिक स्थिति को शामिल करता है। राजनीतिक सशक्तिकरण सामूहिक निर्णय लेने को प्रभावित करने, अधिकारों की वकालत करने, और शासन संरचनाओं में भागीदारी की महिलाओं की क्षमता को समाहित करता है। कानूनी सशक्तिकरण संवैधानिक अधिकारों की जागरूकता, न्याय प्रणालियों तक पहुंचने की क्षमता और शोषण से सुरक्षा को शामिल करता है। मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण आत्म–धारणा, आकांक्षाओं, और अधिकारों और संभावनाओं की चेतना में परिवर्तन को शामिल करता है।

महत्वपूर्ण रूप से, डिजिटल सशक्तिकरण तेजी से अन्य सशक्तिकरण क्षेत्रों में प्रगति को सुविधाजनक बनाने वाले एक सक्षम आयाम के रूप में कार्य करता है। सूचना पहुंच, सामूहिक गतिशीलता के लिए प्लेटफार्मों, आय सृजन के अवसरों और चेतना–वृद्धि के लिए स्थानों को प्रदान करके, डिजिटल मीडिया विकास अवसरों के रूप में संदर्भित करते हैं जो ऐतिहासिक बाधाओं को दूर करने का मार्ग उपलब्ध करवाता है।

डिजिटल मीडिया – एजेंसी और विकल्प का विस्तारित क्षेत्रः डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म् संस्थानिक रूप से बिखरे हुए और पहले सूचना से अलग–थलग आबादियों के बीच एजेंसी और विकल्प–निर्माण को विस्तारित करने के लिए गुणात्मक रूप से विशिष्ट साधन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पारंपरिक विकास हस्तक्षेप के विपरीत जो भौतिक अवसंरचना या संस्थागत पहुंच पर निर्भर करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भौगोलिक सीमाओं में असिंक्रोनस, कम–लागत सूचना विनिमय और नेटवर्क गठन को सक्षम करते हैं। यह क्षमता गतिशीलता प्रतिबंधों, भाषा बाधाओं और औपचारिक शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित पहुंच का सामना करने वाली आदिवासी महिलाओं के लिए विशेष महत्व प्राप्त करता है।

डिजिटल मीडिया की सशक्तिकारी क्षमता विशिष्ट तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैः (1) सूचना पहुंच और जागरूकता विस्तार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी अधिकार, बाजार अवसर और सरकारी योजनाओं के संबंध में पहले अनुपलब्ध ज्ञान प्रदान करनाय (2) नेटवर्क विस्तार और सामाजिक पूंजी संचय, दूरस्थ व्यक्तियों और संगठनों के साथ कनेक्शन सक्षम करना जो सामान्य हितों या आवश्यकताओं को साझा करते हैंय (3) आर्थिक अवसर निर्माण, उद्यमिता, बाजार पहुंच और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सुविधा प्रदान करनाय (4) कौशल अधिग्रहण और मानव पूंजी विकास, ऑनलाइन शैक्षणिक संसाधनों के माध्यम से औपचारिक और अनौपचारिक सीखना सक्षम करनाय (5) चेतना–वृद्धि और राजनीतिक गतिशीलता, सामूहिक

पहचान गठन और अधिकारों के लिए वकालत समर्थन करनाय और (6) आत्म–प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए प्लेटफॉर्म्स। ये सब आदिवासी महिलाओं को बाहरी प्रतिनिधित्व के निष्क्रिय विषय रहने के बजाय अपनी व्यक्तिगत कहानियों के लेखक बनने का विकल्प देते हैं। आलोचनात्मक रूप से, हालांकि, डिजिटल मीडिया की सशक्तिकारी क्षमता आवश्यक क्षमताओं (डिजिटल साक्षरता), सक्षम परिस्थितियों (विश्वसनीय अवसंरचना, सस्ती पहुंच) और समर्थक नीति वातावरण पर निर्भर रहती है। इन परिस्थितियों की अनुपस्थिति मौजूदा असमानताओं को पुनः उत्पादित या तीव्र कर सकती है, जिसे शोधकर्ता ष्डिजिटल विभाजनष् कहते हैंकृ जहां तकनीक तक असमान पहुंच और डिजिटल कौशल सामाजिक स्तरीकरण के व्यापक पैटर्नों को बनाए रखते हैं।

डिजिटल विभाजनः आदिवासी महिलाओं की डिजिटल भागीदारी के लिए बाधाएं

डिजिटल पहुंच और अपनाने के लिए संरचनात्मक बाधाएंः ग्रामीण और आदिवासी भारत डिजिटल पहुंच और कनेक्टिविटी में निरंतर असमानताओं का प्रदर्शन करता है। जबकि शहरी भारत 70 % से अधिक इंटरनेट पारगमन दर प्रदर्शित करता है, ग्रामीण क्षेत्र पर्याप्त रूप से पिछड़े हैं जिसमें कनेक्टिविटी केवल आबादियों का लगभग 50 % तक पहुंचती है। ग्रामीण संदर्भों के अंदर, लैंगिक गतिविधियां इस असमानता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाती हैं। हाल के डेटा के अनुसार, ग्रामीण भारत में, पुरुष इंटरनेट का उपयोग लगभग महिलाओं की दर से दोगुना करते हैं, जो लैंगिक, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, साक्षरता और सांस्कृतिक मानदंडों में निहित अंतर्संबंधी बाधाओं को दर्शाता है।

आदिवासी महिलाओं के लिए विशेषतः, ये बाधाएं कई आयामों में संयोजित होती हैं। सबसे पहले, अवसंरचना सीमाएं भौगोलिक रूप से बिखरे हुए आदिवासी बस्तियों में विश्वसनीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तक पहुंच को प्रतिबंधित करती हैं। दूसरा, आर्थिक बाधाएं उपकरणों (स्मार्टफोन, कंप्यूटर) और न्यूनतम आय पर निर्वाह करने वाले परिवारों के लिए डेटा सेवाओं को पहुंच से बाहर बनाती हैं। तीसरा, लैंगिक–आधारित घरेलू नियंत्रण महिलाओं की साझी घरेलू उपकरणों तक स्वायत्त पहुंच को प्रतिबंधित करता है, पुरुष परिवार के सदस्यों अक्सर महिलाओं की ऑनलाइन गतिविधियों को शासित करते हुए और घरेलू सुरक्षा या महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिए खतरे के रूप में माना जाने वाले उपकरणों तक पहुंच को सीमित करते हैं। चौथा, भाषा बाधाएं डिजिटल नेविगेशन को जटिल बनाती हैं, जैसा कि अधिकांश प्लेटफार्म इंटरफेस और ऑनलाइन सामग्री मुख्य रूप से अंग्रेजी या प्रमुख राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध रहती हैं, न कि स्थानीय आदिवासी भाषाओं में। पांचवां, डिजिटल साक्षरताकृविशिष्ट उद्देश्यों के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों को प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल को सीमित करती हैं।

डिजिटल भागीदारी पर सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएं

संरचनात्मक कारकों से परे, गहराई से निहित सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंड आदिवासी महिलाओं की डिजिटल संलग्नता को सीमित करते हैं। पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचनाएं घरेलू प्रौद्योगिकी के उपयोग पर पुरुष सत्ता को बनाए रखती हैं, कुछ समुदायों के साथ विवाह से पहले महिलाओं की यौन सत्यता के लिए खतरे के रूप में स्मार्टफोन को देखते हैं या विवाह के बाद घरेलू देखभाल की जिम्मेदारी से विचलन के रूप में। ये लैंगिक निगरानी तंत्र महिलाओं की स्वायत्त डिजिटल एजेंसी को प्रतिबंधित करते हैं, भले ही उपकरणों तक शारीरिक पहुंच तकनीकी रूप से उपलब्ध हो।

धार्मिक और पारंपरिक विश्वास उपयुक्त महिला व्यवहार और सार्वजनिक दृश्यमानता के बारे में डिजिटल भागीदारी को जटिल बनाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया संलग्नता पितृसत्तात्मक ढांचों के अंदर महिलाओं के लिए अनुचित ष्सार्वजनिकष् व्यवहार के रूप में माना जा सकता है। अतिरिक्त रूप से, डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से शोषण के संबंध में समस्याएं आदिवासी महिलाओं की यौन हिंसा और आर्थिक जबरदस्ती के प्रति वैध

ऐतिहासिक अनुभवों को प्रतिबिंबित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल सशक्तिकरण पहलों को अवसर विस्तार के साथ सुरक्षा समस्याओं को संबोधित करना आवश्यक है।

डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सशक्तिकरण उत्प्रेरक के रूप में: तंत्र और मार्ग

सूचना पहुंच, जागरूकता विस्तार और अधिकार चेतनाः डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभूतपूर्व सूचना प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं जो आदिवासी महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी अधिकार, सरकारी योजनाओं और बाजार अवसरों के संबंध में पहले अनुपलब्ध ज्ञान तक पहुंच प्रदान करते हैं। व्हाट्सएप, इसके संचार–केंद्रित डिजाइन के बावजूद, एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है जिसके माध्यम से जागरूकता अभियान आदिवासी समुदायों को महिलाओं के अधिकारों, स्वास्थ्य सूचना और सरकारी योजनाओं के संबंध में पहुंचते हैं। वीडियो–आधारित प्लेटफार्मों, विशेषतः यूट्यूब, सीमित साक्षरता वाले व्यक्तियों के लिए पहुंच योग्य आकर्षक सामग्री प्रसारित करते हैं, जिसमें जटिल कानूनी अवधारणाओं, स्वास्थ्य सूचना, और उद्यमिता मार्गदर्शन की व्याख्या करने वाली सचित्र वीडियो शामिल हैं।

विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकारों, अवसरों और संरचनात्मक अन्याय की जागरूकता सशक्तिकरण प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण को समर्थन प्रदान करने के लिए एक आवश्यक शर्त का प्रतीक है। जब आदिवासी महिलाएं लैंगिक हिंसा के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा, शिक्षा के अधिकारया उद्यमिता योजनाओं की जानकारी तक पहुंचती हैं, तो यह सूचना दमनकारी परिस्थितियों के परित्याग से सक्रिय अधिकार पुष्टि की ओरआत्म–धारणा और आकांक्षाओं में बदलाव की संभावना प्रदान करती है। झारखंड की आदिवासी जनसंख्या में सरकारी योजना जागरूकता पर शोध प्रदर्शित करता है कि डिजिटल मीडिया विशेषतः यूट्यूब पर वीडियो सामग्री और व्हाट्सएप् समूह प्रसारकृआदिवासी महिलाओं के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और अन्य योजनाओं के प्रति ज्ञान में पर्याप्त वृद्धि का एक उदाहरण है।

डिजिटल उद्यमिता और बाजार पहुंच के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरणः शायद सबसे मूर्त सशक्तिकरण तंत्र आर्थिक मार्गों के माध्यम से संचालित होता है। डिजिटल प्लेटफार्मोंकृविशेषतः फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप् और उदीयमान ई–कॉमर्स बाजारकृआदिवासी महिला उद्यमियों की आर्थिक भागीदारी को सीमित करने वाली ऐतिहासिक बाधाओं को पार करने में सक्षम करते हैं। परंपरागत रूप से, आदिवासी महिलाओं की आर्थिक गतिविधियां जीवन–निर्वाह कृषि, आहरणकारी वन कार्य, या स्थानीय रूप में शिल्प उत्पादन तक सीमित रहीं, न्यूनतम बाजार पहुंच और अत्यंत सीमित आय–सृजन संभावनाओं के साथ।

डिजिटल प्लेटफार्मों इस परिदृश्य को मौलिक रूप से परिवर्तित करते हैं कम–लागत, भौगोलिक रूप से असीमित बाजार पहुंच प्रदान करते हुए। आदिवासी महिला कारीगर अब हस्तनिर्मित उत्पादों का फोटोग्राफ लेते हैं, उन्हें डिजिटल प्लेटफार्मों पर सूचीबद्ध करते हैं और दूरस्थ ग्राहकों के साथ सीधे संचार करते हैं, शोषक मध्यस्थों को दरकिनार करते हुए जो पहले मूल्य के पर्याप्त अनुपातों को जब्त करते थे। उत्तर गुजरात की आदिवासी महिला उद्यमियों से सर्वेक्षण डेटा प्रकट करता है कि 92 % दैनिक रूप से व्यावसायिक संचार के लिए व्हाट्सएप् का उपयोग करते हैं, 78 % उत्पाद विपणन के लिए फेसबुक नियोजित करते हैं और 65 % दृश्य उत्पाद प्रदर्शन के लिए इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं। इन महिलाओं द्वारा विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपनाने के बाद मासिक आय में 300–500 % की वृद्धि के साथ–साथ बढ़ी वित्तीय स्वायत्तता और पुरुष सदस्यों पर आर्थिक निर्भरता में कमी सशक्तिकरण का द्योतक हैं।

डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से आर्थिक भागीदारी कबीर द्वारा ष्आर्थिक सशक्तिकरणष् की पहचान में योगदान करती है जिसमें आय सृजन, स्वायत्त वित्तीय निर्णय, और संपत्ति संचय की क्षमता शामिल हैं। यह आर्थिक आयाम संवर्धक सशक्तिकरण प्रभाव को उत्प्रेरित करता है जो बढ़ी घरेलू आय, संसाधन आवंटन, घरेलू निर्णय और व्यक्तिगत स्वायत्तता संबंधी महिलाओं की शक्ति को विस्तारित करता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय

स्वतंत्रता घरेलू हिंसा और शोषक संबंधों के लिए महिलाओं की कमजोरी को कम करता है, क्योंकि आर्थिक निर्भरता पितृसत्तात्मक शक्ति को बनाए रखने वाली एक गंभीर तंत्र है।

कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता और कार्य दक्षता

डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों कौशल विकास और मानव पूंजी विकास को कई तंत्रों के माध्यम से सुविधा देते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, प्रशिक्षण मूलक वीडियो और डिजिटल ट्यूटोरियल्स आदिवासी महिलाओं को तकनीकी कौशल, व्यावसायिक ज्ञान और पेशेवर क्षमताएं प्राप्त करने में सक्षम करते हैं जो पहले केवल औपचारिक संस्थागत चैनलों के माध्यम से सुलभ थीं और ये औपचारिक चैनल काफी हद तक दूरस्थ आदिवासी आबादियों के लिए अनुपलब्ध थे। फेसबुक की ग्लोबल ऑनलाइन लीडरशिप पहल विशेषतः पाँच भारतीय राज्यों में आदिवासी लड़कियों को लक्ष्य करती है, डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल नेतृत्व प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए, सीधे 4,000 आदिवासी लड़कियों को डिजिटल–कुशल युवा नेताओं में परिवर्तित करती है।

व्यापक डिजिटल साक्षरता पहल, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ग्रामीण भारत में कुल लाभार्थियों के 54% से अधिक महिलाएं प्रशिक्षण में पर्याप्त पहुंच प्राप्त कर चुकी हैं। ये हस्तक्षेप संवर्धक सशक्तिकरण प्रभाव बनाते हैंः डिजिटल साक्षरता महिलाओं की सरकारी ई–सेवाओं तक पहुंचने की क्षमता में वृद्धि करता है, ऑनलाइन सीखने में भागीदारी प्रशस्त करता है, डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से वित्तीय लेनदेन सुविधा प्रदान करता है और डिजिटल अर्थव्यवस्था में विस्तारित रोजगार अवसर सुविधा प्रदान करता है। आदिवासी महिलाओं के बीच प्रारंभिक डिजिटल साक्षरता अपनाने के लिए ष्डिजिटल राजदूतष् या सामुदायिक प्रशिक्षक के रूप में उदीयमान भूमिकाएं नई स्थिति और आय अवसर बनाती हैं। महिलाएं जिन्होंने डिजिटल सशक्तिकरण फाउंडेशन पहलों के माध्यम से डिजिटल उपकरणों में महारत हासिल की, बाद में पेशेवर प्रशिक्षकों के रूप में, आय सृजन करते हुए अपनी सामुदायिक स्थिति को ऊंचा करते हुए नेतृत्व भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं।

डिजिटल गतिशीलता के माध्यम से राजनीतिक सशक्तिकरण

डिजिटल प्लेटफार्मों दो पूरक तंत्रों के माध्यम से राजनीतिक सशक्तिकरण सक्षम करते हैंः राजनीतिक प्रक्रियाओं में व्यक्तिगत भागीदारी और साझा हितों के संबंध में सामूहिक गतिशीलता। व्हाट्सएप् और फेसबुक जैसे मंच राजनीतिक मुद्दों, अधिकार उल्लंघनों और सामूहिक कार्यों के संबंध में तीव्र सूचना प्रसार सुविधा देते हैं। उत्तर गुजरात की आदिवासी क्षेत्रों में, सोशल मीडिया ने मानव तस्करी को संबोधित करने वाले जागरूकता अभियानों में साधन की भूमिका निभाई तथा सामूहिक रिपोर्टिंग और समर्थन नेटवर्क गठन सक्षम किया। ये डिजिटल–सक्षम सामूहिक कार्य ष्राजनीतिक एजेंसीष् का प्रतिनिधित्व करते हैं जो महिलाओं की सामूहिक निर्णय लेने में भागीदारी करने और उनके समुदायों को प्रभावित करने वाले राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता का निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल मीडिया स्थान प्रदान करता हैंकृ एक ऐसा क्षेत्र जहां हाशिये पर स्थित समूह सामाजिक परिस्थितियों की वैकल्पिक व्याख्या विकसित करते हैं और प्रभुत्वशाली शक्ति व्यवस्थाओं को प्रतिद्वंदिता प्रदान करते हैं। आदिवासी महिलाओं के व्हाट्सएप समूह कार्यस्थल भेदभाव, स्वास्थ्य समस्याएं या भूमिहीनता पर चर्चा वर्चुअल राजनीतिक स्थानों का गठन करते हैं जहां दमित समुदाय एकता बनाते हैं और परिवर्तन के लिए संगठन का निर्माण करते हैं।

आदिवासी महिलाओं के बीच डिजिटल मीडिया के सशक्तिकरण प्रभावः संदर्भात्मक साक्ष्य

विभिन्न शोध आदिवासी महिलाओं, विशेषतः युवा समूहों के बीच डिजिटल प्लेटफार्म अपनाने में पर्याप्त वृद्धि का उल्लेख करते है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और गुजरात की आदिवासी महिलाओं के बीच अध्ययन प्रकट करते हैं कि 80–90 % युवा आदिवासी महिलाएं (18–35 वर्ष की उम्र) स्मार्टफोन धारण करती हैं, जिनके पास

उपकरण हैं उनके बीच व्हाट्सएप उपयोग 90 % से अधिक है। उपयोग पैटर्न प्रकट करते हैं कि आदिवासी महिलाएं इन प्लेटफार्मों को केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं बल्कि आर्थिक, सूचनात्मक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए साधनात्मक रूप से नियोजित करती हैं।

संचार–केंद्रित प्लेटफार्मों की आर्थिक उद्देश्यों में पुनः उपयोग आदिवासी महिलाओं की एजेंसीकृउनकी उत्तरजीविता आवश्यकताओं को संबोधित करने और अवसर–खोज के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की साधनात्मक अनुकूलन का प्रदर्शन करता है। गुजरात की एक आदिवासी महिला उद्यमी ने रिपोर्ट किया, ष्व्हाट्सएप ने मेरे शिल्प को एक व्यवसाय में बदल दिया। शहरों की महिलाएं जो कभी हमारे गाँव नहीं आएंगी, अब व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से सीधे खरीदारी करती हैं। मेरी आय बढ़ी, मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और मेरा परिवार मेरे आर्थिक योगदान का सम्मान करता है। ष्ऐसे उदाहरण से स्पष्ट है कि कैसे डिजिटल उपकरणों को महिलाओं के दैनिक उत्तरजीविता और अवसर–खोज रणनीतियों में बुना जा रहा है।

प्रलेखित सशक्तिकरण परिणाम

तुलनात्मक अध्ययन डिजिटल संलग्नता की अलग–अलग डिग्री वाली आदिवासी महिलाओं की तुलना में मापने योग्य सशक्तिकरण भेदों का साक्ष्य प्रदान करते हैं। झारखंड और उत्तर गुजरात की आदिवासी क्षेत्रों में संचालित मिश्रित–विधि अनुसंधान स्पष्ट करता है कि सक्रिय सामाजिक मीडिया संलग्नता वाली आदिवासी महिलाएं रिपोर्ट करती हैंः (1) बढ़ी घरेलू निर्णय–निर्माण भागीदारी (गैर–उपयोगकर्ताओं में 62 % बनाम 34 %)य (2) कानूनी अधिकारों और सरकारी अधिकारों की बढ़ी जागरूकता (58 % बनाम 28 %)य (3) घरेलू आय में उच्चतर योगदान (12 % के विपरीत औसत घरेलू आय का 35 %)य (4) बढ़ी आत्मविश्वास और एजेंसी (सत्यापित सशक्तिकरण पैमानों के माध्यम से मापी गई)य (5) निर्णय–निर्माण निकायों में बढ़ी सामुदायिक भागीदारीय और (6) तत्काल रिश्तेदारी समूह से परे व्यक्तियों को समाहित करते हुए विस्तारित सामाजिक नेटवर्क।

अनुदैर्ध्य शोध डिजिटल प्लेटफार्म अपनाने के बाद दो–वर्षीय अवधि में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण को ट्रैक करता है, निरंतर प्रभाव प्रकट करता है। प्रारंभिक आर्थिक लाभ समेकित होते हैं क्योंकि महिलाएं विस्तारित उत्पादन, औपचारिक व्यावसायिक पंजीकरण और विविध उत्पाद लाइनों में आय का पुनर्निवेश करती हैं। राजनीतिक भागीदारी भीबढ़ती है क्योंकि महिलाओं की दृश्यमान आर्थिक योगदान बढ़ी घरेलू सत्ता और सामुदायिक सम्मान में परिलक्षित होता है।

बाधाएं और सीमाएंः निरंतर डिजिटल विभाजन

डिजिटल मीडिया की प्रलेखित सशक्तिकारी क्षमता के बावजूद, आदिवासी महिलाओं के लिए डिजिटल मीडिया की रूपांतरकारी क्षमता को सीमित करने वाली पर्याप्त बाधाएं निरंतर विद्यमान हैं। शोध नीतिगत ध्यान की आवश्यकता वाली गंभीर सीमाओं की पहचान करता हैः

- **अवसंरचना और कनेक्टिविटी बाधाएंः** आदिवासी अंचलोंमें विश्वसनीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की कमी है, महिलाओं को स्थिर इंटरनेट पहुंच के लिए शहरी क्षेत्रों की यात्रा करना आवश्यक है। यह बाधा गतिशीलता प्रतिबंधों वाली महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती है।
- **डिजिटल साक्षरता कमीः** हालांकि स्मार्टफोन अपनाने की दर पर्याप्ता बढ़ी है, डिजिटल साक्षरता की कमी निरंतर है। आदिवासी महिलाएँ उद्यमी उन्नत प्लेटफार्म सुविधाओं, वित्तीय लेनदेन, और ऑनलाइन सुरक्षा के संबंध में अपर्याप्त डिजिटल साक्षरता को एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में चिन्हित करती हैं। ये कमी आर्थिक या सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्लेटफार्म कार्यक्षमता को पूरी तरह उपयोग करने के लिए महिलाओं की क्षमता को सीमित करती हैं।

- **लैंगिक पहुंच प्रतिबंधः** स्मार्टफोन धारण करने के बावजूद, आदिवासी महिलाओं को पुरुष रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित करने के प्रयास का अनुभव होता है, जो उनकी गतिविधियों को निगरानी करते हैं, उपयुक्त प्लेटफार्म उपयोग निर्धारित करते हैं, और गैर–रिश्तेदारी व्यक्तियों के साथ संचार को सीमित करते हैं। ये तंत्र तकनीकी पहुंच के बावजूद पितृसत्तात्मक नियंत्रण बनाए रखते हैं।
- **सामग्री और भाषा बाधाएंः** अंग्रेजी और हिंदी–भाषा सामग्रीका प्रभुत्व एकभाषी आदिवासी भाषा वक्ताओं के लिए पहुंच को सीमित करती है। जबकि मंच तेजी से क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करते हैं, सामग्री उपलब्धता, विशेषतः विशेषीकृत विषयों (कानूनी सूचना, स्वास्थ्य मार्गदर्शन, उद्यमिता मार्गदर्शन) के संबंध में अपर्याप्त रहती है।
- **सुरक्षा और सुरक्षा समस्याएंः** आदिवासी महिलाएं डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करते हुए उत्पीड़न, शोषण, और धोखाधड़ी जोखिमों का सामना करती हैं। ऑनलाइन सुरक्षा में सीमित जागरूकता, अपर्याप्त प्लेटफार्म जवाबदेही तंत्र और अपराधियों की दंडरहितता डिजिटल प्लेटफार्म संलग्नता को सीमित करने वाली वैध समस्याओं को बनाता है।
- **वित्तीय बाधाएंः** स्मार्टफोन लागतें घटने के बावजूद, डेटा व्यय जीविका–आय घरों के लिए निषेधात्मक रहते हैं। मासिक डेटा पैकेज खरीदने की आवश्यकता सबसे गरीब आदिवासी महिलाओं को सुसंगत कनेक्टिविटी से बाहर करती है।

पूरक नीति और कार्यान्वयन ढांचे

डिजिटल मीडिया की सशक्तिकारी क्षमता को साकार करने के लिए इन बहुआयामी बाधाओं को संबोधित करने वाली सावधानीपूर्वक नीति समन्वय तथा सक्षम परिस्थितियों को अधिकतम करने की आवश्यकता है।

- **अवसंरचना और कनेक्टिविटी विकासः** व्यापक नेटवर्क कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड अवसंरचना विस्तार को महिलाओं तक पहुंच के लिए विशेष ध्यान के साथ आदिवासी बस्तियों कवरेज को प्राथमिकता देनी चाहिए। कनेक्टिविटी प्रावधान से परे, सामुदायिक–आधारित डिजिटल पहुंच केंद्रोंकृकंप्यूटर, विश्वसनीय इंटरनेट, और प्रशिक्षित समर्थन कर्मचारी से सुसज्जितकृगाँव पंचायतों या स्कूलों पर स्थापित किए जाने चाहिए, विशेषतः महिलाओं के लिए निःशुल्क या सब्सिडीकृत पहुंच प्रदान करते हुए।
- **सांस्कृतिक रूप से संदर्भात्मक डिजिटल साक्षरता प्रोग्रामिंगः** डिजिटल साक्षरता पहल तकनीकी कौशल संचरण से परे सशक्तिकरण आयामों को संबोधित करने वाली क्षमता निर्माण की ओर अगुवाई करनी चाहिए। प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित को शामिल करना चाहिए : महिलाओं की डिजिटल स्वायत्तता पर पितृसत्तात्मक बाधाओं के संबंध में लैंगिक–चेतनाय व्यक्तिगत प्रासंगिकता प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक सार्थक अनुप्रयोगय स्थानीय आदिवासी भाषाओं में सामग्रीय और ऑनलाइन सुरक्षा पर स्पष्ट ध्यान। आदिवासी समुदायों से चिन्हित महिलाओं को प्रशिक्षकों के रूप में व्यवस्थित रूप से समर्थित किया जाना चाहिए, जिसमें आय सृजन करते हुए सांस्कृतिक उपयुक्तता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
- **लैंगिक पहुंच और सुरक्षाः** नीतिगत ढांचों को महिलाओं की स्वायत्त डिजिटल संलग्नता को प्रतिबंधित करने वाली पितृसत्तात्मक नियंत्रण तंत्र को संबोधित करना चाहिए। सामुदायिक संवेदनशीलता पहल महिलाओं की डिजिटल भागीदारी के सशक्तिकारी लाभ को हाइलाइट करना चाहिए, जबकि ऑनलाइन जोखिमों और सुरक्षात्मक रणनीतियों की पारदर्शी चर्चा के माध्यम से सुरक्षा समस्याओं को संबोधित करना चाहिए। प्लेटफार्म जवाबदेही तंत्र में सुधार किया जाना चाहिए, उत्पीड़न और शोषण के प्रति तीव्र प्रतिक्रियाओं के साथ समाधान करना होगा।

- **सामग्री विकास और भाषाः** आदिवासी महिलाओं की विशेष सूचना आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली व्यवस्थित रूप से विकसित सामग्रीकृसुलभ भाषाओं में, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त प्रारूपों में संस्थागत किया जाना चाहिए। सरकारी योजनाएं, स्वास्थ्य सूचना, कानूनी मार्गदर्शन और उद्यमिता संसाधनों को व्यवस्थित रूप से आदिवासी संदर्भों के लिए अनुवादित और अनुकूलित किया जाना चाहिए।
- **वित्तीय समावेशन और सब्सिडीकृत पहुंचः** आदिवासी महिलाओं के लिए लक्षित डेटा सब्सिडी को सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से लागू कर सुसंगत कनेक्टिविटी के लिए वित्तीय बाधाओं को कम करना चाहिए। सरकारी योजनाओं में प्लेटफार्म पहुंच के लिए पूंजी बाधाओं को कम करते हुए, उपकरण वित्तपोषण के प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

डिजिटल मीडिया आदिवासी महिलाओं के बीच सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रेरित करने के लिए शक्तिशाली परन्तु शर्तिया साधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई तंत्रों के माध्यम से सूचना तक पहुंच से चेतना को विस्तारित करते हुए, उद्यमिता आर्थिक स्वतंत्रता सक्षम करते हुए, कौशल विकास क्षमताओं बढ़ाते हुए और डिजिटल गतिशीलता सामूहिक एजेंसी को बढ़ावा देते हुएकृडिजिटल प्लेटफॉर्म्स उन संदर्भों में रणनीतिक जीवन विकल्पों को बनाने की आदिवासी महिलाओं की क्षमता को मौलिक रूप से विस्तारित करते हैं जहां ऐसा विकल्प–निर्माण ऐतिहासिक रूप से सीमित किया गया था। हालांकि, सशक्तिकरण परिवर्तन अनिवार्य या स्वचालिता से दूर रहता है। डिजिटल विभाजन एक योग्य बाधा के रूप में बना रहता है, शिक्षित, आर्थिक संसाधन वाले व्यक्तियों को भिन्न रूप से लाभान्वित, जबकि सबसे गरीब और सामाजिक रूप से अलग–थलग आदिवासी महिलाओं को सीमांत करते हुए। अवसंरचना, डिजिटल साक्षरता, पितृसत्तात्मक पहुंच प्रतिबंध और सुरक्षा समस्याओं को संबोधित करने वाले सचेत नीति हस्तक्षेप के बिना, डिजिटल सशक्तिकरण उन्हें पार करने के बजाय मौजूदा असमानताओं को पुनः उत्पादित करेगा।

जब सहायक परिस्थितियों को पोषित किया जाता हैकृविश्वसनीय कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक रूप से संदर्भात्मक डिजिटल साक्षरता प्रोग्रामिंग, पितृसत्तात्मक बाधाओं को संबोधित करने वाली सामुदायिक गतिशीलता और आदिवासी महिलाओं की आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली सचेत सामग्री विकास तो डिजिटल मीडिया आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, और मनोवैज्ञानिक आयामों में परिवर्तनकारी सशक्तिकरण को प्रेरित करता है। ये परिवर्तन व्यक्तिगत महिलाओं से परे व्यापक सामाजिक परिवर्तन की ओर विस्तृत होते हैं, क्योंकि सशक्त आदिवासी महिलाएं पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देती हैं, नीति प्रतिक्रिया की मांग करती हैं, और वैकल्पिक संभावनाओं की ओर युवा समूहों को प्रेरित करती हैं।

इस परिवर्तनकारी क्षमता को साकार करना समकालीन भारत में एक समावेशी विकास हेतु अनिवार्य है। जैसे–जैसे डिजिटल तकनीकें दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में विस्तार करती हैं, गंभीर प्रश्न यह नहीं है कि क्या डिजिटल मीडिया आदिवासी समुदायों को प्रभावित करेगी, बल्कि यह है कि क्या यह डिजिटल परिवर्तन सशक्तिकरण और समानता का निर्माण करेगी या मौजूदा पदानुक्रम को पुनः उत्पादन करेगी। डिजिटल सशक्तिकरण तंत्र की समझ से निहित और आदिवासी महिलाओं की विशिष्ट संदर्भों के लिए तैयार सावधानीपूर्वक, समावेशीनीति ढांचे सुनिश्चित कर सकते हैं कि डिजिटल मीडिया परिवर्तनकारी सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक प्रामाणिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2021). महिला सशक्तिकरण पर रिपोर्ट. नई दिल्लीः भारत सरकार.

2. नीति आयोग (2018). महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय रिपोर्ट. नई दिल्लीः भारत सरकार.
3. "महिला सशक्तिकरण और सूचना प्रौद्योगिकी" (2019). कुरुक्षेत्र पत्रिका, भारत सरकार.
4. "डिजिटल साक्षरता और ग्रामीण विकास" (2020). योजना पत्रिका, भारत सरकार.
5. मजूमदार, वीना (2004). भारतीय महिला और सशक्तिकरण. नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग, भारत सरकार.
6. आहूजा, राम (2014). भारतीय समाज जयपुरः रावत पब्लिकेशन्स.
7. Kabeer, N. (2005). Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal. Third World Quarterly, [vol- 26] (1) pp- 13&32.
8. Kaur, H. (2024). The Role of Social Media in Empowering Tribal Women to Combat Human Trafficking: A Sociological Study of North Gujarat. Sociological Studies Journal of Applied Research. [vol- 2024] pp. 1-25.
9. Khatoon, A. (2024). Rural and Tribal Women Using Social Media for Cultural Preservation and Economic Empowerment. International Journal of Research and Technology Integration. [vol. 9 (3)] pp. 112-128.
10. Krause, Bonnie L., et al. "Networks and Knowledge: Women's Empowerment and Health Information Participation." Research Review International, vol. 19, no. 2, 2024, pp. 78-95.
11. Mishra, Ranjana, and Aneja, Pramod. "Right to Information and Empowerment of Women." Journal of Women's Rights and Development, vol. 2017, 2017, pp. 1-22.
12. Nussbaum, Martha. Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice. Oxford University Press, 2003.
13. Priya, P., et al. "Two Decades of Theorising and Measuring Women's Empowerment: A Systematic Review." Gender and Development, vol. 29, no. 3, 2021, pp. 445-463.
14. Shaw, Kailas. "Mobile Phone Usage Pattern of Women of Santal Tribe in West Bengal." Journal of Social Science Studies, vol. 2024, 2024, pp. 1-18.
15. Singh, Dhanula Anjali. "Economic Opportunities and Social Media: Tribal Women Entrepreneurs in North Gujarat." Sociological Studies Journal of Applied Research, vol. 2024, 2024, pp. 1-22.
16. Trivedi, Meera, et al. "Tribal Women's Views of Social Media in Healthcare Access and Awareness." Nano Journal of Technology and Innovation, vol. 2024, 2024, pp. 1-20.
17. UN Department for Women. Gender Equality and Empowerment of Women Through ICT. United Nations Division for the Advancement of Women, 2005.
18. UNFPA India. "The Stage Has Been Set for Gender Equity in Digital India." UNFPA India News, 2023.
19. Women's Resource Center. "Women's Empowerment in India and Its Various Dimensions." International Journal of Research and Analysis on Human Issues, vol. 2024, 2024, pp. 1-18.

❑❑❑